

सूचना के अधिकार का सुदृढीकरण

यह संपादकीय 14/10/2024 को द हट्टि में प्रकाशित “[Scuttling people's right to information](#)” पर आधारित है। संपादकीय में RTI अधिनियम को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने की बात कही गई है, जिसमें सरकार की नषिक्रयिता, पक्षपातपूर्ण नयुक्तियों और हाल ही में हुए वधायी परिवर्तनों को मुख्य मुद्दा बताया गया है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिये इन चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर बल देता है।

प्रलिस के लयि:

[सूचना का अधिकार \(RTI\) अधिनियम-2005](#), [डजिटल वयकतगित डेटा संरक्षण अधिनियम- 2023](#), [आपातकालीन अवध](#), [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण \(1975\)](#), [सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम](#), [केंद्रीय सूचना आयोग](#), [वहसिलबलोअर संरक्षण अधिनियम](#), [सामान्य सेवा केंद्र](#)

मेन्स के लयि:

भारत में सूचना के अधिकार का वकिस, RTI की प्रभावशीलता को कमजोर करने वाले मुद्दे।

[सूचना का अधिकार \(RTI\) अधिनियम, 2005](#) पछिले दो दशकों से भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही की आधारशला रहा है। इसने नागरकों को भ्रष्टाचार को उजागर करने और सत्ता को उत्तरदायी ठहराने का अधिकार दया है, जिसमें [बुनयादी अधिकारों के वतरण में अनयिमतिताओं](#) को उजागर करने से लेकर [चुनावी बॉण्ड जैसी अपारदर्शी योजनाओं के पीछे की सच्चाई](#) को उजागर करना शामिल है। हालाँकि, RTI अधिनियम की प्रभावशीलता को वभिन्न तरीकों से व्यवस्थित रूप से कमजोर कया जा रहा है।

सूचना आयुक्तों की नयुक्ति में वलिंब के कारण आयोग नषिक्रयि हो गए हैं, जिससे अपीलों का लंबति मामला बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों की नयुक्ति में सेवानवृत्त अधिकारियों या राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों को प्राथमकता दी जाती है, जिसके कारण वे कानून को सख्ती से लागू करने में अनचिछुक रहते हैं। [RTI अधिनियम में संशोधन](#) और [डजिटल वयकतगित डेटा संरक्षण अधिनियम- 2023](#) में प्रावधानों सहति हाल के वधायी परिवर्तनों ने कानून की शक्ति को और कमजोर कर दया है। जैसा कि हम इस ऐतहासक कानून के 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, RTI अधिनियम में नहिति पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना को बनाए रखने के लिये इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

भारत में सूचना का अधिकार कसि प्रकार वकिसति हुआ है?

- (वर्ष 1975-1977)- पारदर्शिता आंदोलन के बीज: [आपातकालीन अवध](#) के दौरान, नागरिक स्वतंत्रता को नलिंबति कर दया गया था, जिससे सरकार की जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
 - भारतीय लोकतंत्र में इस अवध ने [कार्यकर्त्ताओं और बुद्धजीवियों के बीच सूचना के अधिकार के संदर्भ में चर्चा](#) को जन्म दया।
 - हालाँकि इस समय कोई ठोस वधायी कदम नहीं उठाए गए, लेकिन आपातकाल के अनुभव ने भवषिय में पारदर्शिता संबंधी पहलों के लिये आधार तैयार कया, क्योंकि नागरकों को सरकार की अपारदर्शीता जैसे खतरों का आभास हो गया था।
- वर्ष 1975- सूचना के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण \(1975\)](#) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने [संवधान के अनुच्छेद 19\(1\)\(A\)](#) के तहत वाक् एवं अभवियक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हसिसे के रूप में [सूचना के अधिकार को मान्यता दी](#)।
 - [\[1975\] 2 SCR 529 \(1975\)](#) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दया कि [पारदर्शी सरकार का सदिधांत अनुच्छेद 19\(1\)\(A\)](#) के तहत स्पष्ट वाक् और अभवियक्ति के अधिकार में नहिति जानकारी प्राप्त करने के अधिकार से उत्पन्न हुआ है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि [सरकारी सूचना का प्रकटन](#) आदर्श होना चाहिये तथा गोपनीयता अपवादस्वरूप होनी चाहिये।
- वर्ष 1990- मज़दूर कसान शक्ति संगठन (MKSS) आंदोलन: [राजस्थान में स्थापति MKSS](#) ने स्थानीय सरकारी रकिर्ड तक पहुँच पर ध्यान केंद्रति करते हुए सूचना के अधिकार के लिये ज़मीनी स्तर पर अभयान शुरू कया।
 - उनकी अभनव “[जन सुनवाई](#)” ने सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार को उजागर कया और पारदर्शिता के लिये समर्थन को प्रेरति कया।
 - इस आंदोलन ने [भ्रष्टाचार से लड़ने में सूचना की शक्ति को प्रदर्शति कया](#) और यह पूरे भारत में RTI समर्थन के लिये एक आदर्श बन गया।
- वर्ष 1997-2001-राज्य स्तरीय RTI कानून: तमलिनाडु (वर्ष 1997), गोवा (वर्ष 1997), राजस्थान (वर्ष 2000), कर्नाटक (वर्ष

- 2000), दिल्ली (वर्ष 2001)** सहित कई राज्यों ने अपने स्वयं के RTI कानून बनाए।
- ये राज्य-स्तरीय पहल राष्ट्रीय कानून के अग्रदूत के रूप में कार्य करती हैं तथा कार्यान्वयन में मूल्यवान अनुभव प्रदान करती हैं।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष **2002 में महाराष्ट्र का RTI अधिनियम** विशेष रूप से सुदृढ़ था जो अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श बन गया।
 - इन राज्य कानूनों की प्रभावशीलता अलग-अलग थी, लेकिन इनसे समग्र भारत में पारदर्शिता कानून के लिये जनता की बढ़ती मांग प्रदर्शित हुई।
- वर्ष 2002- सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम:** केंद्र सरकार ने **सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम** पारित किया, लेकिन इसे कभी अधिसूचित नहीं किया गया और इस प्रकार यह कभी लागू नहीं हुआ।
 - इस अधिनियम की आलोचना इसके कमज़ोर प्रावधानों और अनेक छूटों के कारण की गई।
 - इस अधिनियम की वफ़िलता ने एक अधिक व्यापक और नागरिक-अनुकूल कानून की आवश्यकता को उजागर किया।
 - नागरिक समाज संगठन एक सुदृढ़ राष्ट्रीय RTI कानून के लिये दबाव बनाते रहे तथा सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम की कमियों का हवाला देते हुए अधिक सख्त प्रावधानों की मांग करते रहे।
 - वर्ष 2005- सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियम:** RTI अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और अक्टूबर, 2005 में लागू हुआ।
 - इसमें सरकारी सूचनाओं के लिये नागरिकों के अनुरोधों के अनुसार समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश दिया गया, केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना की गई तथा अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया।
 - इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार के सभी स्तर शामिल थे तथा इसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित नज़ि नकिया भी शामिल थे।
 - इस ऐतिहासिक कानून को उस समय विश्व के सबसे प्रगतशील पारदर्शिता कानूनों में से एक माना गया था।
 - वर्ष 2006-2010- प्रारंभिक कार्यान्वयन और प्रभाव** प्रारंभिक वर्षों में RTI आवेदनों में वृद्धि देखी गई, नागरिकों ने भ्रष्टाचार को उजागर करने तथा जवाबदेही की मांग करने के लिये अधिनियम का उपयोग किया।
 - उल्लेखनीय खुलासों में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताएँ शामिल थीं।
 - हालाँकि सूचना आयोगों में लंबित मामलों और नौकरशाही के प्रतिरोध जैसी चुनौतियाँ भी स्पष्ट हो गईं।
 - वर्ष 2011-2019-न्यायिक हस्तक्षेप और विस्तार:** सर्वोच्च न्यायालय के कई नरिणों ने RTI अधिनियम को और सुदृढ़ किया।
 - वर्ष 2013 में, इसने आदेश दिया कि राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाना चाहिये, हालाँकि इस नरिण को कार्यान्वयन में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
 - हालाँकि वर्ष 2011 में शेरला मसूदा जैसी प्रमुख RTI कार्यकर्ता की हत्या ने सूचना मांगने वालों के सामने बढ़ते खतरों को उजागर कर दिया।
 - वर्ष 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का कार्यालय सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है।
 - सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019:** इस संशोधन ने मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (IC) के पूर्व 5-वर्षीय कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा नरिधारित 3-वर्ष के कार्यकाल से प्रतिस्थापित कर दिया।
 - इसने केंद्र सरकार को उनके वेतन का नरिधारण करने की भी अनुमति दे दी तथा उनकी नयुक्ति के बाद पूर्व सरकारी सेवा के लिये पेंशन कटौती को भी हटा दिया।
 - वर्ष 2023 में संशोधन:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 44(3) ने सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को RTI प्रकटन से छूट दे दी है और इसके मोचन (प्रकाशन) की अनुमति देने वाले पछिले अपवादों को हटा दिया है।

RTI अधिनियम की प्रभावशीलता को किस प्रकार कम किया जा रहा है?

- कम कर्मचारी और नषिक्रयि सूचना आयोग:** कई राज्य सूचना आयोग या तो काम नहीं कर रहे हैं या उनमें कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण अपीलें और शकियतों का भारी बोझ बढ़ गया है।
 - सत्रक नागरिक संगठन की रपिर्ट (2023-24) के अनुसार, पछिले वर्ष 29 में से 7 सूचना आयोग अलग-अलग अवधि के लिये नषिक्रयि रहे।
 - झारखंड का आयोग 4 वर्षों से नषिक्रयि है, जबकि त्रपुरा और तेलंगाना क्रमशः 3 वर्षों तथा डेढ़ वर्षों से नषिक्रयि हैं।
 - केंद्रीय सूचना आयोग में 11 में से 8 पद रकित हैं। कर्मचारियों की भारी कमी के कारण पूरे भारत में 4 लाख से भी अधिक अपीलें और शकियतें लंबित हैं। छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे कुछ राज्यों में वर्ष 2029 तक नई अपीलें का नपिटान होने की उम्मीद नहीं है।
- संशोधनों के माध्यम से अधिनियम को जानबूझकर कमज़ोर किया गया:** हाल के वधियी परिवर्तनों ने RTI अधिनियम की शक्तियों को काफी कमज़ोर कर दिया है।
 - वर्ष 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को सभी सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन और सेवानवृत्तिके बाद के लाभों को नरिधारित करने का अधिकार दिया, जिससे संभवतः उनकी स्वायत्तता से समझौता हो सकता है।
 - हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(J) में संशोधन करके सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को प्रकटन से छूट दे दी है तथा पूर्ववर्ती प्रावधान जो व्यापक सार्वजनिक हित होने पर प्रकटन की अनुमति देता था, को हटा दिया है।
 - इन संशोधनों ने प्राधिकारियों के लिये व्यक्तिगत गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सूचना अनुरोधों को अस्वीकार करना आसान बना दिया है, भले ही प्रकटन में अनविर्य सार्वजनिक हित हो।
- गैर-अनुपालन के लिये दंड का अभाव:** सूचना आयोग RTI अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर दंड लगाने में वफ़िल हो रहे हैं, जिससे दण्ड से मुक्ति की संस्कृति बनती जा रही है।
 - सत्रक नागरिक संगठन की रपिर्ट से पता चलता है कि आयोगों ने 95% मामलों में जुरमाना नहीं लगाया, जहाँ जुरमाना लगाया जा सकता था।
 - गैर-अनुपालन के लिये परिणामों की यह कमी सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को कानून तोड़ने के लिये प्रोत्साहित करती है, जिसके

परिणामस्वरूप आवेदन अधूरे रह जाते हैं, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है या अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकृत कर दिये जाते हैं।

- एक सख्त दंड प्रणाली का अभाव समय और सटीक सूचना प्रकटन सुनिश्चित करने में अधिनियम की प्रभावशीलता को कमज़ोर करता है।
- सूचना आयोगों में राजनीतिक नयिकृतियाँ और विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि सूचना आयोगों में नयिकृत अधिकारिण व्यक्तियाँ तो सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी होते हैं या राजनीतिक संपर्क वाले व्यक्ति होते हैं, जिससे आयोगों की स्वतंत्रता/पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - अपने राजनीतिक सहयोगियों या पूर्व सहकर्मियों को बचाने की प्रवृत्ति के कारण, आयुक्त विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की कमी के परिणामस्वरूप पारदर्शिता नियम के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने में अनिच्छुक हो सकते हैं।
 - शिक्षा जगत, नागरिक समाज या पत्रकारिता जैसे विविध पृष्ठभूमियों से प्रतिनिधित्व का अभाव, सूचना अनुरोधों, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील अनुरोधों पर नए दृष्टिकोण लाने और सख्ती से जाँच करने की आयोगों की क्षमता को सीमित करता है।
 - इसके अलावा, एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने के बाद संदेश भर में सूचना आयुक्तों में से केवल 9% महिलाएँ हैं।
- RTI कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धमकियाँ और हिसा: RTI कार्यकर्ताओं के लिये खतरनाक माहौल अधिनियम की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित करता है।
 - ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार, RTI अधिनियम का उपयोग करने के कारण लगभग 100 लोगों को घातक नुकसान पहुँचाया गया है तथा हजारों लोगों पर हमला किया गया है, धमकी दी गई है या उन्हें झूठे मामलों का सामना करना पड़ा है।
 - इस मुद्दे को हल करने के लिये वर्ष 2014 में पारित [वहसिल-बलोअर संरक्षण अधिनियम](#), सरकार द्वारा आवश्यक नियम बनाने में विफलता के कारण अब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।
 - भय के इस माहौल के कारण, कई नागरिक RTI आवेदन दाखिल करने या अपील करने से कतराते हैं, विशेषकर जब वे शक्तिशाली हतियों से जुड़े संवेदनशील मामलों से निपटते हैं। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को उजागर करने में अधिनियम की क्षमता सीमित हो जाती है।
- प्रकटन से छूट संबंधी प्रावधानों का बढ़ता प्रयोग: सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना साझाकरण को रोकने के लिये RTI अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन से छूट संबंधी प्रावधानों का तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं।
 - व्यक्तिगत सूचना प्रकटन से छूट के दायरे का विस्तार करने वाला हालिया संशोधन इसका प्रमुख उदाहरण है।
 - इसके अतिरिक्त, अधिकारी प्रायः सूचना के अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित धारा 8(1)(A) या वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित धारा 8(1)(D) का हवाला देते हैं।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में सरकार ने इन छूटों का हवाला देते हुए पीएम कैबिनेट फंड के संदर्भ में विवरण देने से इनकार कर दिया। प्रकटन से छूट के प्रावधानों की उदार व्याख्या की यह प्रवृत्ति उस पारदर्शिता को बहुत हद तक कम कर रही है जिस प्रोत्साहन देने के लिये अधिनियम बनाया गया था।
- तकनीकी चुनौतियाँ और डिजिटल डिविड/वभिद: यद्यपि डिजिटलीकरण ने कुछ मायनों में सूचना तक पहुँच में सुधार किया है, लेकिन इसने नई बाधाएँ भी उत्पन्न की हैं।
 - कई सरकारी वेबसाइटों का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया है, उनमें पुरानी या अधूरी जानकारी है।
 - ऑनलाइन RTI दाखिल करने की प्रक्रिया में वे लोग शामिल नहीं हो पाए हैं जिनके पास डिजिटल साक्षरता या इंटरनेट कनेक्शन का अभाव है।
 - IMAI-कानूतार अध्ययन का अनुमान है कि वर्ष 2023 तक लगभग 665 मिलियन भारतीयों, या देश की 45% आबादी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था।
 - यह डिजिटल डिविड सूचना असमानता का एक नया रूप उत्पन्न कर रहा है, जो सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच के अधिनियम के लक्ष्य के विपरीत है।

RTI की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- नयिकृत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और त्वरित करना: केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्तों की नयिकृति के लिये पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता है।
 - विधि और योग्य नयिकृतियाँ सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र चयन समिति की स्थापना करने की आवश्यकता है जिसमें वपिक्षी सदस्य, नागरिक समाज के प्रतिनिधि एवं वधि विशेषज्ञ शामिल हों।
 - यह अनविर्य है कि रिक्रतियों की एक नरिदषिट समय-सीमा के भीतर भरती की जाए, संभवतः पद रिक्रत होने से 30 दिनि पूरव।
 - इस उपाय से आयोगों में कर्मचारियों की कमी के वर्तमान संकट का समाधान होगा तथा नयिकृति प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा।
- डिजिटल अवसंरचना और पहुँच को बढ़ाना: सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में RTI आवेदनों पर नज़र रखने और प्रसंस्करण समय को कम करने के लिये आवेदनों को कुशलतापूर्वक वर्गीकृत एवं उनका प्रबंधन करने के लिये कृत्रमि बुद्धमिर्त्ता को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
 - डिजिटल डिविड को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में RTI कियोस्क (Kiosk) स्थापति करने तथा सामान्य सेवा केंद्रों का प्रयोग करते हुए मोबाइल RTI सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।
 - इस डिजिटल परिवर्तन से पहुँच में सुधार होगा, प्रसंस्करण समय कम होगा तथा RTI आवेदनों की नगिरानी के लिये अधिक पारदर्शी तंत्र स्थापति होगी।
- दंड प्रावधानों और प्रवर्तन को मज़बूत बनाना: RTI अधिनियम में संशोधन करके उन अधिकारियों के लिये अनविर्य दंड का प्रावधान किया जाना चाहिये जो बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर सूचना देने से इनकार करते हैं या इसमें वलिंब करते हैं।
 - व्यक्तिगत जवाबदेही की एक प्रणाली लागू की जानी चाहिये, ताकि बार-बार उल्लंघन से अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड और पदोन्नति की संभावनाएँ भी प्रभावित हो सकें।

- RTI अधिनियम के गंभीर उल्लंघनों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये सूचना आयोगों के भीतर एकस्वतंत्र प्रवर्तन शाखा की स्थापना की जाने की आवश्यकता है।
- इन उपायों से गैर-अनुपालन के वरिद्ध अधिक सख्त नयित्त्रण सुनिश्चित होगा तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा मल्लिगा।
- **RTI कार्यकर्त्ताओं के लिये व्यापक सुरक्षा लागू करना:** RTI कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा के लिये दृढ़ प्रावधानों के साथवहसिल-ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को लागू कथिा जाना चाहयि।
 - धमकी या उत्पीडन का सामना करने वाले RTI उपयोगकर्त्ताओं के लिये एक समरपति हेल्पलाइन और त्वरति प्रतक्रियिा प्रणाली स्थापति कथिा जाना चाहयि।
 - RTI कार्यकर्त्ताओं पर हमलों के मामलों से नपिटने के लिये राज्य स्तर पर एक वशिष जाँच इकाई का गठन कथिा जाने की आवश्यकता है, ताकतिवरति और नषिपकष जाँच सुनिश्चिति हो सके।
 - RTI उपयोगकर्त्ताओं को नुकसान पहुँचाने या उन्हें धमकाने के दोषी पाए जाने वालों के लिये अनुकरणीय दंड के प्रावधान कथिा जाना चाहयि। ये कदम RTI कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा के संदर्भ में बढ़ती चतिाओं को दूर करेंगे और अधिक नागरकिों को बनिा कसिी भय के अधिनियम का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहति करेंगे।
- **अनविर्य सक्रयि प्रकटन और ओपन डेटा पहल:** RTI अधिनियम की धारा 4(1)(B) का वसितार कर सख्ती से इसे लागू कथिा जाने की आवश्यकता है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के सक्रयि प्रकटन को अनविर्य बनाता है।
 - 'डफिॉल्ट रूप से ओपन' नीति लागू कथिा जाने चाहयि, जहाँ सभी गैर-संवेदनशील सरकारी डेटा स्वचालति रूप से मशीन-पठनीय प्रारूप में सार्वजनिक कर दयि जाएँ।
 - सक्रयि प्रकटन मानदंडों का पालन करने में वफिल रहने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिये दंड का प्रावधान कथिा जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टकिण से व्यक्तगति RTI आवेदनों की आवश्यकता कम हो जाएगी और शासन में खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा मल्लिगा।
- **नयिमति प्रशकिषण और कषमता नरिमाण:** जन सूचना अधिकारयिों (PIO) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारयिों के लिये RTI अधिनियम के प्रावधानों, हालयिा न्यायकि घोषणाओं तथा सर्वोत्तम क्रयिान्वयन पर अनविर्य, नयिमति प्रशकिषण कार्यक्रम शुरु करने की आवश्यकता है।
 - ज्ञान और कषमता के उच्च मानक को सुनिश्चिति करने के लिये PIO हेतु प्रमाणन कार्यक्रम वकिसति कथिा जाना चाहयि।
 - युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिये स्कूलों और कॉलेजों में आरटीआई साक्षरता कार्यक्रम शुरु की जानी चाहयि। नागरकिों, वशिष रूप से ग्रामीण और हाशयि के समुदायों के लिये RTI अधिनियम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये समय-समय पर कार्यशालाएँ आयोजति की जानी चाहयि।
 - इन पहलों से RTI प्रतक्रयिाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा तथा नागरकिों को अधिनियम का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता मल्लिगी।
- **प्रकटन से छूट संबंधी प्रावधानों को संशोधति और स्पष्ट करना:** दुरुपयोग और अत्यधिक व्यापक व्याख्याओं को रोकने के लिये RTI अधिनियम की धारा 8 में प्रकटन से छूट संबंधी प्रावधानों की समीक्षा कर उनमें सख्ती लाने की आवश्यकता है।
 - प्रकटन से छूट प्राप्त करने के लिये अनविर्य 'हानिकारक परीक्षण' लागू कथिा जाए, जसिके तहत प्राधिकारयिों को प्रकटन से होने वाली वशिषि, पर्याप्त हानिको प्रदर्शति करने की आवश्यकता होगी।
 - 'व्यापक सार्वजनिक हति' अधरिोहति खंड के अनुप्रयोग पर स्पष्ट दशिा-नरिदेश स्थापति की जानी चाहयि।
 - वर्गीकृत दस्तावेजों की समय-समय पर समीक्षा का आदेश देना चाहयि ताकति ऐसी जानकारी को गोपनीयता से मुक्त कथिा जा सके जसिे अब संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
 - इन संशोधनों से प्रकटन से छूट के मनमाने उपयोग को सीमति कथिा जा सकेगा तथा पारदर्शिता की भावना को बनाए रखा जा सकेगा।
- **RTI वभिागों और अधिकारयिों के प्रदर्शन मूल्यांकन से जोडने की आवश्यकता है।**
 - सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों की वार्षकि रपिोर्ट में RTI नषिपादन को शामिल करना अनविर्य कथिा जाए।
 - शासन प्रक्रयिाओं और सार्वजनिक सेवा वतिरण में प्रणालीगत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये RTI अनुप्रयोगों से प्राप्त अंतरदृष्टिका उपयोग कथिा जाना चाहयि।
 - इस एकीकरण से पारदर्शिता के लिये संस्थागत प्रोत्साहन उत्पन्न होगा तथा शासन में नरितर सुधार के लिये RTI को एक उपकरण के रूप में उपयोग कथिा जा सकेगा।

नषिकरष:

चूँकि हम आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगाँठ मनाने जा रहे हैं, इसलिये पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना को बनाए रखने के लिये इसके सामने आने वाली चुनौतयिों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है। आरटीआई अधिनियम की प्रभावशीलता को केवल तत्काल सुधारों और भारत में सूचना के अधिकार को लेकर सामूहिक प्रतबिद्धता के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है।

Q. भारत में शासन और जवाबदेही पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रभाव पर चर्चा कीजयि। आपके वचिर में, हाल के वर्षों में आरटीआई फरेमवरक के सामने कौन-सी प्रमुख चुनौतयिों हैं और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये इन चुनौतयिों का समाधान कसि प्रकार कथिा जा सकता है?

Q. सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के संदर्भ में नहीं है, यह अनविरय रूप से जवाबदेही की अवधारणा को पुनः परिभाषित करता है।” चर्चा कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/reinforcing-the-right-to-information>

